an>

Title:Need to conduct a fresh census of BPL families in Gujarat in order to facilitate extension of various government schemes to them.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) ः भारत की आबादी में गरीबों का अनुपात हमेशा विवाद में रहा है। सत्ता प्रतिÂठान और नीति-नियंताओं की दिलचस्पी सदा इस बात की रही है कि देश में गरीबी को कम से कम और तेजी से घटते हुए दिखाया जाए ताकि प्रचलित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं की प्रासंगिकता नजर आए। सामाजिक, आर्थिक जनगणना के नतीजों ने इसकी पुÂिट की है। वÂाऱ 2011 में सामाजिक व आर्थिक आयाम को भी शामिल किया गया। इस जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में एक तिहाई परिवार गरीब हैं और ऐसा हर पांचवा परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखता है। ग्रामीण भारत के सवा तेरह फीसद परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। बी.पी.एल. के आंकड़े कुछ भी हो, असंगठित क्षेत्र की रोजगार असुरक्षा और कृÂिा क्षेत्र के व्यापक संकट से गरीबी को मापने के अब तक अपनाए जाते रहे पैमानों पर सवालिया निशान लगा दिया है और जो गणना अब तक हुई है, उसमें हुई गड़बड़ी के कारण बी.पी.एल. में आने वाले बहुत लाभार्थी वंचित रह गये हैं और जनगणना में बहुत गड़बड़ी हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों की पुनः गणना करायी जाए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाआंो का लाभ सभी बी.पी.एल. परिवारों को मिल सके।